

दिनांक 9 नवम्बर, 1987

सं. ओ. वि./गुडगांव/123-86/43986.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० चेयरमैन मार्किट कमेटी, गुडगांव के श्रमिक श्री रामानन्द शर्मा मारफ़्त महा सचिव डी. आर. कुमार ब्रदर्स इम्प्लॉईज यूनियन 5/1 शिवाजी नगर, गुडगांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के संबंध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं :—

क्या श्री रामानन्द को वेतन में वृद्धि मांगोत्रा तथा ओर है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 10 नवम्बर, 1987

सं. ओ. वि./भिवानी/235-87/45033 --चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० भिवानी टेक्सटाईल मिलज भिवानी के श्रमिक श्री अदालती प्रसाद, पुत्र श्री मरत प्रसाद मारफ़्त मजदूर सभा (रजि०) एटक आफिस 43-लेवर कालोनी भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-अम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित हैं :—

क्या श्री अदालती प्रसाद ने स्वयं अनुपस्थित होकर नौकरी से लियन खोया है या उसकी सेवाएं समाप्त की गई है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/भिवानी/184-87/44046.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० भिवानी टेक्सटाईल मिलज भिवानी के श्रमिक श्री फुले खाँ, पुत्र श्री महमूद खाँ मारफ़्त मजदूर सभा (रजि०) एटक आफिस 43-लेवर कालोनी, भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-अम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित हैं :—

क्या श्री फुले खाँ ने स्वयं अनुपस्थित रहकर नौकरी पर से लियन खोया है या उसकी सेवाएं समाप्त की गई है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ.डी./161-84/44053.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० एथोन इन्जी० लि०, 13 माईम स्टोन मथुरा रोड फरीदाबाद के श्रमिक श्री धर्मपाल सिंह, पुत्र श्री उदे सिंह डबुआ कालोनी सैक्टर-2 एन० आई० टी. फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के संबंध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 78 के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे लिखित मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद में सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन माम में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री धर्मपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/भिवानी/180-87/44060.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० रामा फाईवर्ज लि., बामला, (भिवानी), के श्रमिक श्री उमेश सिंह, मार्फत वस्त्र उद्योग मजदूर मंच, 116, लेबर कालोनी, भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन माम में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद में सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री उमेश सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/भिवानी/193-87/44066.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० रामा फाईवर्ज लि., बामला (भिवानी), के श्रमिक श्री राजपाल, पुत्र श्री मातु राम, मार्फत वस्त्र उद्योग मजदूर मंच, 116 लेबर कालोनी, भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन माम में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद में सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री राजपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/भिवानी/178-87/44073.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० रामा फाईवर्ज लि., बामला, (भिवानी), के श्रमिक श्री गजानन्द, पुत्र श्री जिले सिंह, मार्फत वस्त्र उद्योग मजदूर मंच, 116 लेबर कालोनी, भिवानी तथा प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573,

दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री गजा नन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ० वि०/भिवानी/179-87/44080.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० रामा फाईवर्ज लि., बामला, भिवानी, के श्रमिक श्री केवल कृष्ण, पुत्र श्री राधे श्याम, द्वारा वस्त्र उद्योग मजदूर संघ, 116 नेबर कालोनी, भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री केवल कृष्ण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किम राहत का हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,

उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

The 3rd December, 1987

No. 5626-ET-III-87/36189.—Shri S. N. Bajaj, Excise and Taxation Officer, Sirsa, retired from Government service on the after noon of the 30th November, 1987.

No. 5626-ET-III-87/36193.—Shri K. K. Sayal, Excise and Taxation Officer, Gurgaon, retired from Government service on the afternoon of the 30th November, 1987.

S. N. PURI,

Joint Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT

The 4th December, 1987

No. P. S. Election-L A 2-87/409.—In pursuance of the provision of sub-section (i) of section 12 of the Punjab Panchayat Samiti Act, 1961 (Punjab Act No. 3 of 1961), it is hereby notified that Shri Abdul Rashid, S/o Moj Khan, Sarpanch Gram Panchayat Kamara and Shri Chote Lal, S/o Ghoshi Panch, (S. C.) Gram Panchayat Nimkhera, Block Ferozepur Jhirka, District Gurgaon have been nominated as a Primary Member of Panchayat Samiti, Ferozepur Jhirka, District Gurgaon against the vacancies caused due to resignation and death of Primary Members respectively.

L. M. GOYAL,

Chandigarh dated the
4th December, 1987

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.